भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं : मूलभूत दृष्टिकोण
(INDIA'S FIVE YEAR PLANS : BASIC APPROACH)

रंभिक पंचवर्षीय योजनाएं
Earlier Five Year Plans)

पहली पंचवर्षीय योजना में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह किसी मॉडल पर आधारित है, परन्तु जब हम इस जना के बचत सम्बन्धी अनुमानों, निवेश की राशियों, पूँजी-उत्पाद अनुपात (capital-output ratio) तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि अलपकालीन लक्ष्यों के साथ-साथ दीर्घकालीन लक्ष्यों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि **यह योजना हैरॉड-डोमर कास मॉडल पर आधारित होते हुए भी उससे थोड़ी-सी भिन्न है।** हैरॉड-डोमर मॉडल के अनुसार यदि किसी देश में पूँजी-उत्पाद नुपात तथा बचत-आय अनुपात स्थिर हैं तो विकास की दर को स्थिर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में जी-उत्पाद अनुपात 3:1 है और बचत की दर राष्ट्रीय आय की 18 प्रतिशत है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि अथवा विकास की दर $8 \times 1/3 = 6$ प्रतिशत होगी। **हैरॉड-डोमर मॉडल में पहली पंचवर्षीय योजना में एक सुधार किया गया है। हैरॉड-डोमर मॉडल में चत की औसत दर और सीमांत दर को बराबर स्वीकार किया गया है जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में बचत की सीमान्त दर को सत दर से अधिक माना गया है।** मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ बचत की दर ऊंची उठेगी जिससे प्रत्येक ई योजना की प्रगति के साथ-साथ विकास की दर ऊंची होती जाएगी। इस मॉडल का प्रधान दोष यह है कि यह अर्थव्यवस्था की ंचा सम्बन्धी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता और विकास प्रक्रिया को पूंजी निर्माण की दर का नतीजा मानता है। इस प्रकार ह विकास में आने वाली वास्तविक कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देता है।[1]

दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों में निवेश पर विशेष जोर दिया गया। वास्तव में औद्योगिक त्र में निवेश का स्वरूप महलानबीस (P.C. Mahalanobis) के विकास मॉडल से काफी प्रभावित था। बीसवीं शताब्दी के तीसरे शक में सोवियत संघ में यही मॉडल फैल्डमैन (R. Feldman) ने तैयार किया था। इस मॉडल में चालू निवेश को दो भागों में बांटा या : प्रथम, पूँजीगत माल तैयार करने वाले क्षेत्रों में निवेश, तथा द्वितीय, उपभोग की वस्तुएं उत्पादित करने वाले क्षेत्रों में निवेश। हलानोबिस के द्विक्षेत्रीय मॉडल में निवेश का पूँजीगत माल बनाने वाले क्षेत्र में अनुपात विकास की दर का महत्वपूर्ण निर्धारक है। जीगत माल उत्पादित करने वाले उद्योगों में निवेश जितने अधिक होंगे विकास की दर उतनी ही अधिक ऊंची रहेगी।[2] बहुत-सी ातों को ध्यान में रखते हुए दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर भी जोर दिया गया। इस प्रकार दूसरी योजना में औद्योगीकरण की जो युक्ति अपनाई गई उसके महत्वपूर्ण तत्त्व निम्नलिखित थे :

(*i*) **निवेश की दर में वृद्धि करना क्योंकि विकास की दर इसी तरह निर्भर करती है;**

(*ii*) **अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्ति (productive power) में तीव्र वृद्धि लाने के दृष्टिकोण से भारी व पूँजीगत वस्तु उद्योगों में भारी निवेश करना; तथा**

(*iii*) **सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व एवं कार्यक्षेत्र में विस्तार करना ताकि यह अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित कर सके।**[3]

दूसरी योजना में अपनाई गई औद्योगीकरण की युक्ति के इन तत्वों को भारत की विकास-युक्ति के मूल तत्व माना जा सकता है। बाद की योजनाओं में भी इन्हें विकास-युक्ति के मूल तत्व माना गया है हालांकि आवश्यकता [illegible]

Scanned with CamScanner

जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, तीसरी और चौथी योजना में, दूसरी योजना की अपेक्षा, कृषि व सहायक गतिविधियों को अधिक महत्व देने की बात कही गई। **परन्तु 1970 तक आते-आते आयोजकों के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है।** 1971 में वी.एम. दांडेकर तथा नीलकंठ रथ के महत्वपूर्ण अध्ययन *Poverty in India* के कारण तथा अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा किये गये आलोचनात्मक विवेचन के कारण यह बात स्पष्ट हो गई कि आयोजन के दो दशकों के बाद भी देश में भयानक गरीबी व्याप्त है। **यह कटु सत्य कि 40 प्रतिशत जनसंख्या जीवन का न्यूनतम-स्तर प्राप्त कर पाने में भी असफल रही है सभी को झकझोरने के लिए काफी था। इसलिए आयोजन की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों पर दोबारा नजर डालना जरूरी हो गया।** इसलिए पहली बार योजना आयोग के *Approach Paper of the Fifth Plan* में पुनर्वितरण की एक योजना की सिफारिश की गई। इसके अन्तर्गत देश के सबसे धनी 30 प्रतिशत वर्ग के प्रति व्यक्ति उपभोग-स्तर को कम करने की व्यवस्था थी ताकि सबसे निर्धन 30 प्रतिशत वर्ग के प्रति व्यक्ति उपभोग-स्तर को बढ़ाया जा सके। लक्ष्य यह रखा गया कि पांचवीं योजना के आखिरी वर्ष तक गरीबी दूर हो जाएगी तथा उपभोग वितरण में असमानताएं कम हो जाएंगी। अन्तिम वर्ष के लिए समष्टि अर्थशास्त्रीय (macro-economic) लक्ष्य जैसे पूंजी-निर्माण, निर्यात, आयात इत्यादि के लक्ष्य इस ढंग से निर्धारित किए गए कि उनका कुल उपभोग के लक्ष्य के साथ तालमेल हो।[4]

परन्तु कई राजनैतिक व आर्थिक कारणों से 'पुनर्वितरण' की योजना को लागू नहीं किया जा सका। इस देश में राजनैतिक व सामाजिक स्तर पर धनी वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली है और उससे यह उम्मीद करना कि वह आय व उपभोग-स्तर में कमी के लिए राजी हो जाएगा, व्यर्थ है। वस्तुतः राजनैतिक शक्ति भी इसी वर्ग के हाथ में है। आर्थिक आधार पर सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि 'पुनर्वितरण' कैसे किया जाए यह स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा देश के सबसे धनी 30 प्रतिशत वर्ग में बहुत से मध्यमवर्गीय और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार भी आ जाते हैं। इनके उपभोग-स्तर में कमी करने से बहुत सी समस्याएँ पैदा हो सकती थीं। इन सब बातों के कारण **पांचवीं योजना के मसौदे में 'पुनर्वितरण' का यह प्रयास छोड़ दिया गया। हालांकि पुनर्वितरण की बात अवश्य की गई परन्तु पुनर्वितरण की कोई स्पष्ट योजना पेश नहीं की गई।**

छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी के निवारण, लाभदायक रोजगार अवसरों के सृजन तथा तकनीकी व आर्थिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को महत्त्व दिया गया। यह भी कहा गया कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तेज आर्थिक संवृद्धि होना आवश्यक है। परन्तु क्योंकि तेज आर्थिक संवृद्धि के लाभ स्वतः गरीब जनता को प्राप्त नहीं होते, इसलिए इस योजना में कुछ विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा कुछ अन्य गरीबी निवारण के कार्यक्रम अपनाये गये। जहां तक संवृद्धि दर का सम्बन्ध है, प्रारम्भिक अवरोधों (constraints) को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया कि अर्थव्यवस्था 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष से ज्यादा संवृद्धि दर प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए आर्थिक संवृद्धि का लक्ष्य 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)
(Seventh Five Year Plan, 1985-90)

सातवीं योजना के मुख्य उद्देश्य वही थे जिनका उल्लेख पहले की योजनाओं में किया गया था। इस तरह इस योजना में भी संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर जोर था। लेकिन इस बात को समझते हुए कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक न्याय की दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं हुई, योजना आयोग ने सातवीं योजना में इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति होनी चाहिए और रोजगार विस्तार और गरीबी निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्पादक रोजगार से लोगों में आत्मविश्वास पैदा होता है और इससे उनकी विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ जाती है। रोजगार के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोजक अब रोजगार में विस्तार के लिए महज आर्थिक संवृद्धि पर निर्भर नहीं रहना चाहते। **सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसलिए रोजगार को एक सीधा और अपने आप में महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना गया था। लेकिन योजना आयोग की राय में रोजगार को स्थायी रूप से बनाये रखने के लिए उसका उत्पादक होना जरूरी है। तात्पर्य यह है कि रोजगार में विस्तार के द्वारा उत्पादन और आय में निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए।**

छठी योजना शुरू होने के समय ऊर्जा और यातायात समस्याएं काफी गंभीर रूप धारण किए हुए थीं। इनकी वजह से सारी विकास प्रक्रिया में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यह स्थिति इन क्षेत्रों में भारी निवेश के बावजूद पैदा हो गई थी! सातवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि आधारभूत ढांचे (infrastructure) में जो भी निवेश किया हो उसका उचित नतीजा निकले। ऐसा होने पर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में आने वाली कुछ बाधाएं दूर हो सकती हैं।

Scanned with CamScanner